टोक्यो में भारत-जापान वस्त्र साझेदारी

कपड़ा सचिव नीलम शमी राव ने टोक्यो में जापानी उद्योगपतियों और निवेशकों से की मुलाकात

नई दिल्ली, , 16 जून भारत और जापान के बीच कपड़ा और परिधान क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा सचिव नीलम शमी राव के नेतृत्व में सोमवार को टोक्यो में जापान के कपड़ा और परिधान क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

मंत्रालय के अनुसार, जापानी कंपनियों ने भारत में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने, भारतीय विनिर्माण इकाइयों के साथ साझेदारी करने और भविष्य की तकनीकी परियोजनाओं में सहयोग करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की.

कपड़ा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जानकारी साझा करते हुये कहा कि कपड़ा सचिव की यह यात्रा दोनों देशों के बीच कपड़ा व परिधान क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और आधुनिक तकनीक के आदान-प्रदान में बढ़ोतरी के उद्देश्य से आयोजित की गयी है. दोनों देश एक-दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं. श्रीमती राव ने इस अवसर पर कहा कि भारत वैश्विक कपड़ा बाजार में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है. भारत के पास उपलब्ध कुशल श्रमशक्ति, प्रचुर कच्चा माल और सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसी सहायक नीतियां जापानी निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं. इस साझेदारी से न केवल दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी भी मजबूत होगी.

श्रीमती राव के साथ वस्त्र मंत्रालय का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान गया है. भारतीय प्रतिनिधिमंडल में श्रीमती राव के साथ देश के कपड़ा उद्योग के कई प्रमुख उद्योगपति और नीति निर्माता भी शामिल हैं.

अब सूचीबद्ध होगा एनएसई, आईपीओ को लेकर जबरदस्त उत्साह

नई दिल्ली, 16 जून. भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) जल्द ही अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (प्रारंभिक दस्तावेज) दाखिल कर सकता है. इसके बाद इसके बहुप्रतीक्षित आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

सूत्रों के अनुसार, एनएसई के आईपीओ का मूल्यांकन 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. इससे यह भारत के सबसे बड़े और सबसे चर्चित आईपीओ में शामिल हो जाएगा. इस खबर के बाद निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. फिलहाल एनएसई के शेयर अनलिस्टेड बाजार में 2,000 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. इसमें कई बड़ी संस्थाओं की हिस्सेदारी है.

आरबीआई में सीधी भर्ती, मिलेगा डेढ़ लाख

बिना परीक्षा चयन, विशेषज्ञ युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

भारतीय रिजर्व बैंक ने यंग प्रोफेशनल के 12 पदों पर आवेदन मांगे

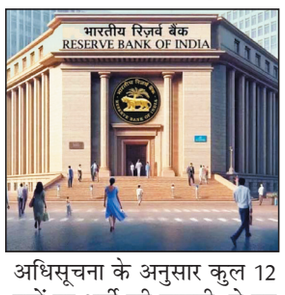

नई दिल्ली, 16 जून भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों में युवा पेशेवर (यंग प्रोफेशनल) पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं.

इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को किसी लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के आधार पर पूरी की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा.

आरबीआई की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 12 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये पद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन जैसे विशेष क्षेत्रों से संबंधित हैं. इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवाओं को देश की शीर्ष वित्तीय संस्था के साथ काम करने का अवसर मिलेगा.

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति पूर्णकालिक संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर होगी. इसे नियमित सरकारी नौकरी या स्थायी नियुक्ति नहीं माना जाएगा. चयनित उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से तीन वष के लिए नियुक्त किया जाएगा. आवश्यकता और आपसी सहमति के आधार पर संविदा अवधि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कुल कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा.

आरबीआई का उद्देश्य नई तकनीकों और उभरती चुनौतियों से जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञ पेशेवरों की सेवाएं लेना है. इसके लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में तकनीकी योग्यता, अनुभव और विशेष कौशल होना जरूरी है. केंद्रीय बैंक का मानना है कि इन क्षेत्रों के वित्तीय प्रणाली को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी का बड़ा दांव

भारत में एआई और डेटा सेंटर उपकरणों के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनेगा

अगले 7 वर्षों में 3 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक बाजार को लक्ष्य बनाया गया

नई दिल्ली, 16 जून. अडानी एंटरप्राइजेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसऔर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अमेरिकी कंपनी जैबिल के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है. इस साझेदारी का उद्देश्य भारत में एआई डेटा सेंटर और उससे जुड़े उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म तैयार करना है.

इस खबर के बाद मंगलवार को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में तेजी देखने को मिली. निवेशकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते कंपनी के शेयर में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.

इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में मल्टी-गीगावाट क्षमता वाला मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा. यहां एआई रैक, सर्वर, स्टोरेज सिस्टम और नेटवर्किंग उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा, जो डेटा सेंटर संचालन के लिए जरूरी हैं. इसके अलावा डेटा सेंटर से जुड़े सहायक उपकरण भी बनाए जाएंगे, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर और थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम. कंपनी का लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं बल्कि वैश्विक बाजार है. अनुमान है कि आने वाले 7 वर्षों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का बाजार 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हो सकता है.

भारत में भी डेटा सेंटर उद्योग तेजी से बढ़ रहा है. अनुमान है कि 2030 तक देश की क्षमता 5 से 8 गीगावाट तक पहुंच सकती है. इसका कारण एआई का बढ़ता उपयोग, क्लाउड सेवाओं की मांग और डेटा लोकलाइजेशन की जरूरत है. अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि दुनिया अब 'एआई क्रांति' के दौर में प्रवेश कर रही है, जो पिछली औद्योगिक क्रांतियों से भी बड़ा बदलाव ला सकती है.

डीजल-पेट्रोल निर्यात शुल्क में भारी वृद्धि

नई दिल्ली, 16 जून सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है. डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है. वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें मंगलवार से लागू होंगी. निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा. वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है. इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे.

दुनिया के सुंदरतम एयरपोर्ट्स में भारत सबसे आगे

नई दिल्ली, 16 जून. भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सात सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की प्रतिष्ठित सूची में भारत के दो हवाई अड्डों ने स्थान बनाया है.

पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में घोषित प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्साय वास्तुकला एवं डिजाइन पुरस्कार 2026 के तहत नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (टर्मिनल-2) इस वैश्विक सूची में शामिल किए गए हैं. यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2026 की इस सूची में भारत से केवल इन्हीं दो हवाई अड्डों को स्थान मिला है. दोनों हवाई अड्डों का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान भारत की आधुनिक बुनियादी ढांचा क्षमता और तेजी से विकसित हो रहे विमानन क्षेत्र की वैश्विक पहचान को और मजबूत करेगा.

प्रिक्स वर्साय पुरस्कार विश्वभर में उत्कृष्ट वास्तुकला, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है.

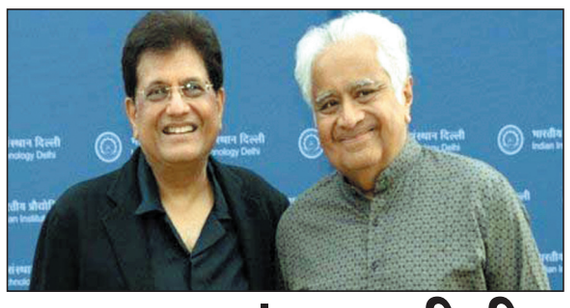

भारत-फ्रांस तकनीकी साझेदारी को नई गति

फ्रांसीसी कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील.

'इंडिया इनोवेट्स 2026' में 350 से अधिक निवेशक शामिल

नई दिल्ली, 16 जून. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और फ्रांस के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और दोनों देशों के संबंध तकनीक, नवाचार और रणनीतिक क्षेत्रों में नए स्तर पर पहुंच रहे हैं. उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों और निवेशकों से भारत के विकास सफर में भागीदार बनने की अपील की.

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने फ्रांस में आयोजित एक रात्रिभोज कार्यक्रम में भाग लिया, जिसकी मेजबानी वरिष्ठ विधिवेत्ता और आईआईटी दिल्ली बोर्ड के अध्यक्ष हरिश सालेव ने की. इस दौरान भारतीय और फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और नवाचार विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच सहयोग अब केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, तकनीकी और नवाचार क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर रहा है.

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई ऊर्जा मिली है. यह साझेदारी न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत कर रही है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए अवसर पैदा कर रही है.

उन्होंने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक नवाचार और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और विदेशी निवेशकों के लिए अपार अवसर उपलब्ध हैं. भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र नई साझेदारियों और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है, जिससे न केवल भारत और फ्रांस बल्कि वैश्विक समुदाय को भी लाभ मिलेगा.

सोने का भाव गिरा, चांदी 4400 रुपये सस्ती

नई दिल्ली, 16 जून. भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते कीमती धातुओं के दामों पर दबाव देखने को मिला.

24 कैरेट सोने के भाव में नरमी आई, जबकि चांदी के दाम में करीब ?4,400 प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है.

जानकारी के अनुसार, सोने के दाम पिछले सत्र की तुलना में नीचे आ गए हैं और 24 कैरेट सोना अपने हालिया उच्च स्तर से फिसलकर कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में भी समान रूप से गिरावट देखी गई है.

ई-श्रम पोर्टल से जुड़े 1.54 करोड़ श्रमिक

82.40 लाख महिला श्रमिकों ने कराई भागीदारी, पुरुषों से अधिक संख्या

कृषि क्षेत्र के लगभग 86 लाख श्रमिक पोर्टल से जुड़े.

जयपुर, 16 जून. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया ई-श्रम पोर्टल राजस्थान में लगातार प्रभावी साबित हो रहा है.

राज्य में अब तक 1 करोड़ 54 लाख 50 हजार 294 श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं. इनमें 82 लाख 40 हजार 291 महिलाएं और 72 लाख 9 हजार 896 पुरुष शामिल हैं. महिलाओं की 53.33 प्रतिशत भागीदारी राज्य में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी बढ़ती सक्रियता को दर्शाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए वर्ष 2021 में ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य देशभर के श्रमिकों का एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार राज्य में कृषि क्षेत्र के सबसे अधिक 85 लाख 99 हजार 316 श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है.

कैश की कमी नहीं, फिर एटीएम क्यों खाली

नई दिल्ली, 16 जून देशभर में कई लोगों को एटीएम पर 'नो कैश' का बोर्ड देखने को मिल रहा है. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या देश में नकदी की कमी हो गई है? हालांकि, सरकारी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस धारणा को गलत साबित करते हैं. आरबीआई के अनुसार, देश में चलन में मौजूद मुद्रा लगातार बढ़ रही है और अप्रैल 2026 तक यह 42.56 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है.

समाचार विशेष

राघव लॉरेंस त्रिची ईस्ट से लड़ेंगे उपचुनाव!

वीडियो शेयर कर राजनीति में एंट्री को लेकर किया ऐलान

चेन्नई. थलपति विजय के करीबी और तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर राघव लॉरेंस राजनीति में एंट्री करने वाले हैं! सुपरहिट रेबेल और कंचना फ्रेंचाइजी जैसी फिल्में बना चुके राघव ने शुक्रवार को राजनीति में आने का ऐलान किया है. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और अपने इस कदम पर जनता की राय मांगी है.

राघव लॉरेंस की यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब यह चर्चा हो रही है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) आने वाले उपचुनाव में उन्हें तिरुचिरापल्ली ईस्ट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है. यह उपचुनाव पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के इस्तीफे के कारण हो रहा है. हालांकि, राघव ने वीडियो के आखिर में यही कहा है कि यह कोई पक्का ऐलान नहीं है, बल्कि वह लोगों की राय जानने के बाद ही कोई आखिरी फैसला लेंगे.

सोशल मीडिया पर राघव लॉरेंस ने एक लंबा 18 मिनट का वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने बताया है कि राजनीति उनके जीवन में कैसे आई. उन्होंने कहा, बिना किसी उम्मीद के ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, मैं इसी सोच के साथ जीता हूं. वह बताते हैं कि इसकी शुरुआत 2017 में जल्लीकट्टू के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी. वहां उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन गई थी, जबकि उनका मकसद सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना था. राघव लॉरेंस सुपरस्टार रजनीकांत को अपना मेंटर मानते हैं. वीडियो में उन्होंने उस वक्त का जिक्र किया है जब उन्होंने रजनीकांत के राजनीति में आने का सपोर्ट किया था.

नाम बदलने का कारण

राघव लॉरेंस को एक कोरियोग्राफर के तौर 4 फिल्मफेयर अवॉर्ड साउथ, 3 नंदी अवॉर्ड और 2 तमिलनाडु राज्य फिल्म अवॉर्ड मिल चुके हैं. राघव लॉरेंस के पिता का नाम मुरुगैयान और मां का नाम कनमनी है. बचपन में उन्हें ब्रेन ट्यूमर था. वे अपने ट्यूमर के ठीक होने का श्रेय देवता राघवेंद्र स्वामी को देते हैं और भक्ति भाव में ही उन्होंने 2001 में अपना नाम राघव रखा है. उन्होंने अवादी-अंबत्तूर रूट पर तिरुमल्लैवायल में राघवेंद्र स्वामी वृंदावनम मंदिर भी बनवाया है.

अल्पसंख्यक मंत्रियों की संख्या कम होगी

नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी की सरकार में कई सालों से कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है. देश की करीब 15 फीसदी आबादी का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है. वैसे भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को लोकसभा की टिकट भी नहीं दी थी.

राज्यसभा में भी कोई मुस्लिम नहीं है. इससे पहले एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे लेकिन दोनों बारी बारी से सरकार से बाहर हो गए. दोनों की राज्यसभा की सदस्यता गई तो फिर नहीं मिली. अब ऐसा लग रहा है कि सरकार में ईसाई मंत्री भी नहीं रहेंगे. केरल के रहने वाले जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं. लेकिन उनको मध्य प्रदेश से इस बार राज्यसभा की टिकट नहीं मिली है. ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने उनको रिटायर करने की तैयारी कर ली है. वे नरेंद्र मोदी की सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री हैं. अगर उनको राज्यसभा नहीं मिलती है तो वे सरकार से बाहर हो जाएंगे.

बिहार के मंत्री का अनोखा रिकॉर्ड

पटना. बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वे दो बार मंत्री बने और दोनों बार किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर 2025 में एनडीए की सरकार के गठन के समय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सबको चौंकाते हुए अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया था.

उनकी पार्टी के चार विधायक जीते थे, जिनमें एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी थीं. माना जा रहा था कि वे उनको मंत्री बनवाएंगे लेकिन उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवाया, जो उस समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे. तब कहा गया था कि मंगल पांडेय विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं तो वे विधान परिषद की सीट खाली करेंगे और उस सीट पर दीपक प्रकाश को भेजा जाएगा. हालांकि भाजपा ने अपने कोटे की यह सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए नहीं छोड़ी.

दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बने रहे इस बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ. नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उनकी जगह सम्राट चौधरी मंत्री बने.

नीतीश ने 14 अप्रैल को इस्तीफा दिया. उसी दिन उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का इस्तीफा हो गया. इस तरह दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य रहे 20 नवंबर से 14 अप्रैल तक यानी करीब पांच महीने तक मंत्री रहे.

इस बीच भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया. तब कहा गया कि अब दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बनेंगे. लेकिन सात मई को जब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो फिर दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया.

इस बार कहा गया कि विधानसभा सदस्यों द्वारा नौ विधान पार्षद चुने जाने हैं उनमें से एक सीट दीपक प्रकाश को मिलेगी. लेकिन उन नौ उम्मीदवारों में दीपक प्रकाश को जगह नहीं मिली. हालांकि अब भी वे सात नवंबर तक मंत्री रह सकते हैं. लेकिन उस समय तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है इसलिए उनको इस्तीफा देना होगा. उनके अनोखे रिकॉर्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है.

विशेष — बीजेपी का दावा- हमनें नहीं तोड़ी टीएमसी!

कौन है मास्टरमाइंड? जिसने उड़ाई ममता की नींद

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़ा राजनीतिक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है. चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गंभीर मुश्किलों में फंस गई है. करीब 15 साल तक राज्य की सत्ता में रहने वाली टीएमसी अब अपने ही सांसदों और विधायकों के विद्रोह का सामना कर रही है. जिससे ममता बनर्जी की राजनीतिक स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है.

दिलचस्प बात ये है कि बंगाल में टीएमसी की मुख्य प्रतिद्वंदी दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस टूट में अपना हाथ होने से इनकार किया है. बीजेपी का कहना है कि यह टूट ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई मनमानी का नतीजा है. टीएमसी के नेताओं की आवाज को उनकी ही पार्टी में दबाया गया. जिसके चलते अब वो इससे बाहर हो रहे है. बीजेपी के बयान के बाद सलाव उठता है कि, अगर बीजेपी नहीं तो फिर वो कौन है जिसने टीएमसी में इतनी बड़ी बगावत को अंजाम दिया?

ऋतब्रत बनर्जी ने की बगावत की शुरुआत- टीएमसी को सबसे बड़ा झटका विधानसभा में लगा है. चुनाव के बाद पार्टी के पास कुल 80 विधायक थे. लेकिन अब इनमें से 65 विधायकों ने बगावत का ऐलान कर दिया. इन बागी विधायकों ने मिलकर एक नया समूह बना लिया है और ऋतब्रत बनर्जी को अपना नेता चुना है. शुरूआत में ऋतब्रत को ही इस बगावत का कर्ता-धर्ता माना जा रहा था. लेकिन फिर कुछ ही दिनों साफ हो गया कि वो तो बस इस बड़ी राजनीतिक उठा-पटक का एक छोटा सा हिस्सा हैं. टीएमसी में संकट केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है. संसद में भी टीएमसी की स्थिति कमजोर होती जा रही है.

टीएमसी के टूटने में किसका हाथ?

इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे कई नेताओं की भूमिका की चर्चा हो रही है. सबसे ज्यादा चर्चा डॉ काकोली घोष दस्तीदार की हो रही है. माना जा रहा है कि काकोली दिल्ली में सांसदों के बीच हुए विद्रोह को संगठित करने में उनकी अहम भूमिका रही है. उन्होंने लंबे समय से असंतुष्ट सांसदों को एकजुट किया और उन्हें एक अलग पहचान देने का प्रयास किया. कहा जा रहा है कि उनका मकसद पार्टी के अंदर बहुमत हासिल कर खुद को असली टीएमसी के रूप में पेश करना है. टीएमसी की टूट में दूसरा बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी का है. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख चेहरा बनने से पहले अधिकारी लंबे समय तक टीएमसी की हिस्सा रह चुके थे.